अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि और समाचार पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई

777. **श्री रणजीत सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में आयातित अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि करने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी की गई है और इस प्रकार की वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सितम्बर-दिसम्बर, 1990 की अवधि के लिए आबंटित अखबारी कागज के कोटे की संबंधित समाचारपत्रों को अभी तक सप्लाई नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और समाचारपत्रों को इसकी सप्लाई कब तक कर दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) आयातित अखबारी कागज की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय तथ्यों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता ।

जनवरी-मार्च, 1991 की तिमाही के लिये स्टैंडर्ड और ग्लेज्ड अखबारी कागज की कीमत क्रमश: 12.280 रुपये और 17,645 रुपये प्रति मी० टन तय की गयी थी, जबकि इससे पूर्व की तिमाही में यह क्रमश: 11,800 रुपये और 16,650 रुपये प्रति मी० टन थी ।

(ग) और (घ) अखबारी कागज की सप्लाई निरंतर जारी रहती है और कागज, अखबारी कागज आबंटन नीति, 1990-91 के अनुसार आबंटित किया जा रहा है ।

विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली हिन्दी पत्रिकाएं

778. **श्री रजनी रंजन साहू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली हिन्दी पत्रिकाओं के क्या नाम हैं और उनके सम्पादन, मुद्रण तथा बिक्री के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ;

(ख) ऐसी पत्रिकाओं के नाम क्या हैं; जिनमें सम्पादकीय पद पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं और ऐसी पत्रिकाओं के नाम क्या हैं, जिनकी पांच सौ से कम प्रतियां निकलती हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ऐसी पत्रिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए किन कदमों पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और राज्य सभा के पटल पर रखी जायेगी ।

राजभाषा अधिनियम का पालन न किया जाना तथा उसकी उपेक्षा

779. **श्री रजनी रंजन साहू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों में राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ;

(ख) राजभाषा अधिनियम के उपबंधों के गैर-अनुपालन/उपेक्षा की स्थिति में उनके कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ;

(ग) विशेष रूप से ऊर्जा, प्रजल संसाधन, तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों में ऐसे